जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 15 संख्याः 230 प्रभात हिण्डौन सिटी, बुधवार 21 जून, 2023 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

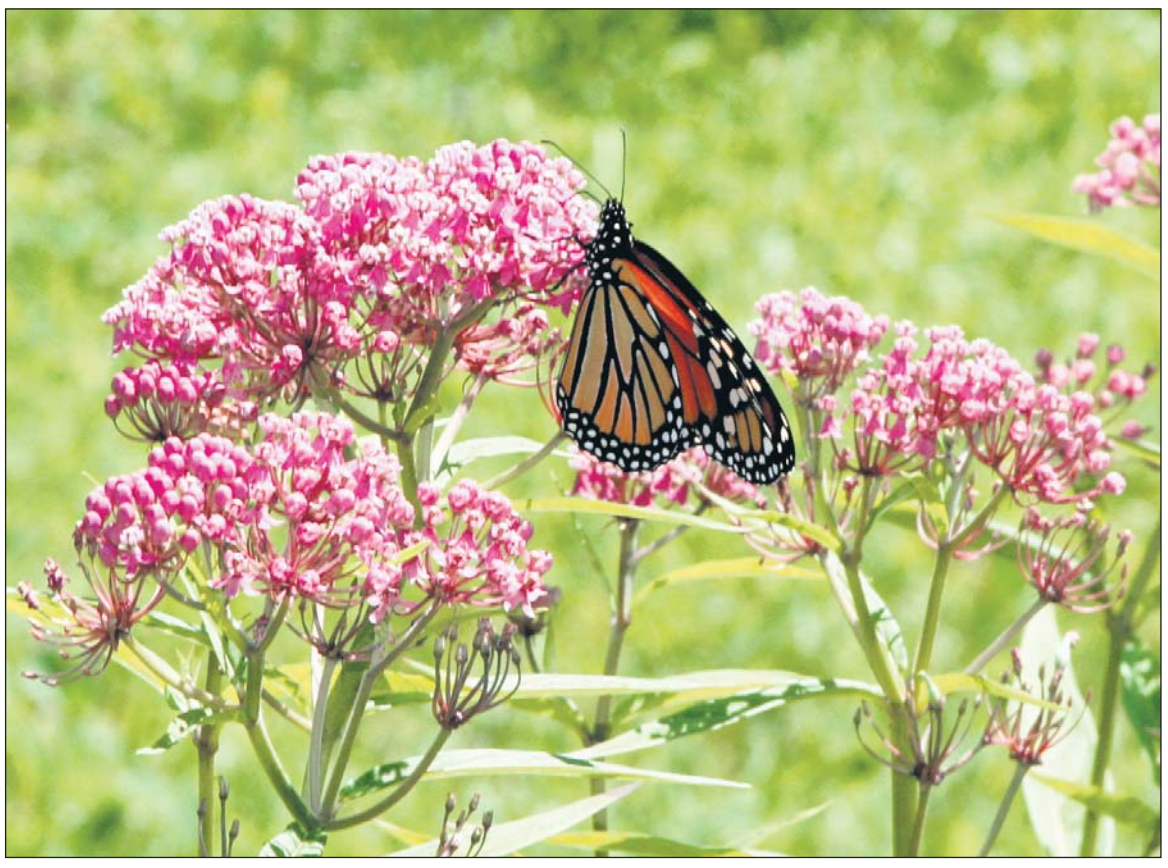

यू.एस. फिश एण्ड वाइल्डलाइफ सर्विस ने टैक्सस में गुलाबी रंग के एक खूबसूरत जंगली फूल के सरवाइवल की गारंटी देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। विभाग ने एक महीने पहले ही, मोनार्क बटरफ्लाई के भोजन के प्रमुख स्रोत प्रॉस्ट्रेट मिल्कवीड के लिए भी ऐसा ही किया था। टैक्सस में शहरी विस्तार के कारण वर्षों से ब्रैंक्टेड ट्विस्टफ्लावर कम होते जा रहे हैं, लेकिन, अब यहां की चार काउंटीज़ में 1600 एकड़ क्षेत्र को इस प्रजाति का ''क्रिटिकल हैबिटैट'' निर्दिष्ट किया गया है। इसका अर्थ है कि यहाँ इन पौधों को कोई छू भी नहीं सकता है। पहाड़ी भागों में मिलने वाले ट्विस्टफ्लावर अब सिर्फ दो क्षेत्रों में ही मिलते हैं और फलने -फूलने के लिए इन्हें धूप-छांव के प्राकृतिक मिश्रण की जरुरत होती, जो इन्हें यहाँ उगने वाले ओक (बलूत) व जूनियर वृक्षों से मिलता है। यह टैक्सस में पाई जाने वाली मधुमक्खी की एक प्रजाति का प्रिय भोजन है। एन्डेन्जर्ड स्पीशीज़ लिस्ट में आने के बाद ट्विस्टफ्लावर को एक तरह से गारंटी मिल गई है कि यह प्रजाति बच जाएगी। क्योंकि इस लिस्ट में रखे जाने के बाद 99 प्रतिशत की दर से प्रजातियों में आ रही गिरावट रुकी है। प्रॉस्ट्रेट मिल्कवीड को भी संरक्षण दिया गया है और इन्हें 661 एकड़ का क्षेत्र मिला है जहां इन्हें संरक्षित किया जाएगा। यहां इस पौधे को काटना, तोड़ना नुकसान पहुंचाना तोड़कर बाहर ले जाना प्रतिबंधित होगा। सैन्टर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की वरिष्ठ वैज्ञानिक, टिएरा करी ने कहा कि, मिल्कवीड का संरक्षण मोनार्क तितली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसी पौधे पर अण्डे देती हैं।

22 जून को राहुल के आगमन से पहले कांग्रेस ने पटना सम्मेलन का एजेण्डा तय करना शुरू किया

कांग्रेस का मैसेज साफ है, कांग्रेस को गाली देना व गठबंधन की बात करना एक साथ नहीं चल सकता

- कांग्रेस का इशारा, केजरीवाल व ममता बनर्जी की ओर है।
- जैसा कि विदित ही है, केजरीवाल चाहते हैं कि, कांग्रेस, पंजाब व दिल्ली केजरीवाल के लिये छोड़ दे, तो फिर केजरीवाल मध्य प्रदेश व राजस्थान कांग्रेस के लिये छोड़ देंगे।
- केजरीवाल, कांग्रेस का समर्थन व सहयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लाये जा रहे अध्यादेश के विरोध में भी चाहते हैं।
- कांग्रेस की दिल्ली इकाई, आम आदमी पार्टी की दो मुंही पॉलिसी, एक तरफ गुर्राना तथा दूसरी तरफ पुचकारना, के सख्त खिलाफ है।
- इसी प्रकार बंगाल प्रदेशाध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन भी बंगाल में, एक तरफ तो कांग्रेस को निगलने की तथा दूसरी ओर सहयोग की बात करने की, तृणमूल कांग्रेस की नीति की पूरी तरह खिलाफत कर रहे हैं।
- तेईस जून को पटना में विपक्ष की एकता का नारा लेकर आगे बढ़ने के प्रयास के रास्ते में अभी काफी ''इनोवेशन'' की जरूरत दिख रही है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बहुप्रचारित बैठक से पहले कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाना शुरु कर दिया है।

कांग्रेस ने साफ कर दिया कि विपक्ष की एकता कांग्रेस की कीमत पर नहीं हो सकती है।

पार्टी ने केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा कि वे कांग्रेस की खिलाफत करने के साथ विपक्षी एकता की बात नहीं कर सकते है।

केजरीवाल ने कांग्रेस से कहा है कि वह दिल्ली और पंजाब से दूर रहे है बदले में उनकी पार्टी राजस्थान और मध्यप्रदेश से दूर रहेगी। ज्ञातव्य है कि आप पार्टी इन दोनों राज्यों में पैर जमाने की कोशिश कर रही है।

केजरीवाल को केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन चाहिए। वहीं अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता केजरीवाल को समर्थन देने का विरोध कर रहे हैं।

कांग्रेस ने विपक्षी दलों में अपने ''मित्रो'' को चेतावनी दी कि उन्हें नरेन्द्र मोदी और उनकी शैली की राजनीति की राज्यों में नकल नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का मत है कि विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ मोदी की तानाशाही शैली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

राहुल के 22 जून को दिल्ली आने की संभावना है। विपक्षी दलों को लेकर मीडिया में भी काफी चर्चा है क्योंकि इसमें एकजुट होने व 2024 के चुनावों में मोदी का मुकाबला मिलकर करने की रणनीति बनाई जाएगी।

क्या ''मोदी हटाओ'' नारा काम करेगा और क्या विपक्ष को और ज्यादा नए तरीके अपनाने और नई सोच व नए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या अमेरिका भारत को ''बैस्ट फ्रैण्ड'' की उपाधि से नवाज़ेगा?

यूक्रेन युद्ध के पहले राष्ट्रपति पुतिन की चीन यात्रा में दोनों देशों ने ''हर दम हमेशा'' बिना सीमा के ''बैस्ट फ्रैण्ड'' रहने का वादा किया था

- यह संभावना इस बात की द्योतक है कि, विश्व में पुराने दिग्गज महत्वहीन होते जा रहे हैं तथा नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की ओर देख रहा है अमेरिका।
- मोदी की अमेरिका यात्रा में कई नयी टैक्नॉलजी ट्रांसफर के अनुबंधनों पर हस्ताक्षर होंगे तथा अमेरिका आधुनिकतम हवाई जहाज इंजन बनाने की टैक्नॉलजी देने को तैयार है। ऐसा विश्वास अमेरिका केवल यूरोप के पुराने गहरे मित्रों पर रखता था, टैक्नॉलजी ट्रांसफर के लिये।
- अमेरिका का प्राइवेट सैक्टर भी भारत से जुड़ने को तैयार है, इलैक्ट्रिक कार व इलैक्ट्रिक कार के लिये जरूरी, बैटरी बनाने वाले, उद्योगपति एलन मस्क भी मोदी से इस संबंध में मिलेंगे।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। इस उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल के दो पहलू महत्वपूर्ण रूप से उभरे हैं।

पहला तो है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में स्थापित करना। यह एक कूटनीतिक कवायद है। दूसरा लक्ष्य ज्यादा व्यवहारिक है और देश की आर्थिक स्थिति के लिए तुरंत लाभदायक है।

मोदी की यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग विशेषज्ञ कम्पनी से एविएशन एवं स्पेस सैक्टर के लिए अत्याधुनिक इंजन के निर्माण के लिए तकनीका का हस्तांतरण होगा। इस यात्रा में अमेरिका की प्रमुख कंपनियों की निर्माण इकाइयां भारत शिफ्ट किए जाने पर भी चर्चा होगी।

इससे भारत पश्चिम और खासकर अमेरिका से ज्यादा निकटता से तालमेल कर सकेगा। यह एक दीर्घकालिक योजना है जिसका भावी सरकार नई वैश्विक व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

भारत तथा प्रमुख पश्चिमी ताकतें समझती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था खत्म हो रही है। एक नयी व्यवस्था धीरे-धीरे उभर रही है जिसमें पश्चिम के कई प्रमुख देशों का महत्व भविष्य में कम हो जाएगा।

इस नहीं व्यवस्था में चीन अपने आक्रामक तेवरों के कारण मुख्य खलनायक है। हालांकि एंटनी ब्लिंकन की हालिया चीन यात्रा के बाद अमेरिका व चीन में तालमेल के कुछ संकेत मिल है, पर संदेह भी भारी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है!
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस लम्बित हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। अदालतों के विचाराधीन केसों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा 5,00,39,981 हो गई है।

भारत का विशाल लीगल सिस्टम लगातार बढ़ते मुकदमों के बोझ से त्रस्त है। देश भर की सभी अदालतों में विचाराधीन मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। बैकलॉग केसों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई इसे देखकर दामिनी फिल्म में सनी देओल द्वारा बोला गया वही डायलॉग याद आता है....''तारीख पर तारीख मिली लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड! इंसाफ नहीं मिला....मिली है तो सिर्फ तारीख''

- नैशनल जुडिशल डेटा ग्रिड ने बताया है कि, 4.38 करोड़ से ज्यादा केस जिला एवं निचली अदालतों में पैंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में 68,000 से ज्यादा केस हैं।

नैशनल जूडिशियल डेटा ग्रिड ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

2025 तक ट्रकों में ड्राइवर का केबिन एयरकण्डिशन होना लाजमी होगा

परिवहन मंत्री की हैसियत से गडकरी ने आदेश पारित किये

- क्या गडकरी को यह निर्णय लेने की प्रेरणा, राहुल गांधी की अमेरिका में ट्रक ड्राइवर के साथ उसके केबिन में लम्बी यात्रा व वार्तालाप करने से मिली।
- यह भी उल्लेखनीय है कि, हाल ही में राहुल गांधी ने अंबाला से चण्डीगढ़ भी ट्रक में ड्राइवर से बातचीत करते हुए यात्रा की थी।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। सड़क परिवहन को उन्नत बनाने की एक कार्यवाही के अन्तर्गत, केन्द्रीय सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि शीघ्र ही, ऑटो-निर्माताओं को ट्रकों के ड्राइवर-केबिन के अंदर एयर-कंडीशनर लगाने होंगे।

यहाँ ऑटो इण्डस्ट्री के एक समारोह में नितिन गडकरी ने कहा, ''आज इस समारोह में आने से पहले, मैंने उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जिसमें ट्रक ड्राइवर केबिनों में एयरकन्डीशनिंग अनिवार्य कर दी गई है। हमें यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि ट्रक चलाने वालों को अच्छी सुविधा प्रदान की जायें।''

सूत्रों ने कहा कि ट्रक ड्राइवरों के लिये एयरकन्डीशन्ड केबिन अनिवार्य करने का विचार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाल ही की उस ऑडियो क्लिप से पैदा हुआ, जब इस महीने के शुरु में उन्होंने अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर के पास बैठकर यात्रा की थी। इस क्लिप में कांग्रेस नेता को उस ट्रक ड्राइवर के साथ लम्बी बातचीत करते हुये दिखाया गया है तथा वे भारत में ट्रक ड्राइविंग की समस्याओं पर चर्चा करते हुये सुने जा सकते हैं। पिछले महीने के शुरु में, वे एक ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक में बैठकर अम्बाला से चंडीगढ़ गये थे तथा इस दौरान उन्होंने देश के ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं के बारे में उस ट्रक ड्राइवर से बातें की थीं।

गडकरी कहीं से भी प्राप्त नये विचारों को स्वीकार करने के लिये जाने जाते हैं। सूत्रों ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी व्यक्तिशः ट्रक ड्राइवरों के साथ ट्रक में यात्रा करके, ड्राइवरों की समस्याओं को सबके सामने लाये, उससे गडकरी बहुत प्रभावित हुये थे।

गडकरी ने कहा, ''हमारे ड्राइवर 43 से 47 डिग्री के ऊँचे तापमान पर ट्रक चलाते हैं और ड्राइवरों की स्थिति की कल्पना करनी चाहिये। मंत्री बनने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस साल कोई लोकसभा उप चुनाव नहीं होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। पिछले शुक्रवार, 16 जून 2023 को 17वीं लोकसभा ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर लिए। ज्ञातव्य है कि, 17 जून 2019 को वर्तमान लोकसभा का पहला सत्र आहूत हुआ था एवं भारत के संविधान के अनुसार, लोकसभा का कार्यकाल उस तारीख से पांच साल तक चलेगा, जिस तारीख को उसकी पहली मीटिंग (सत्र) आहूत की गई, उससे अधिक नहीं। लिहाजा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 तक है। अब, यदि समय

- 5 लोकसभा सीटें रिक्त हैं, लेकिन वर्तमान लोकसभा के 5 वर्षीय कार्यकाल के चार साल पूरे हो चुके हैं और यह अंतिम वर्ष शुरू हो चुका है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आई.एस.आई. का सुनियोजित प्लान है मोदी की अमेरिका यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने का

आई.एस.आई. ने खालिस्तान समर्थक व भारत विरोधी ग्रुप्स में काफी पैसा बांटा है, मोदी की यात्रा के दौरान कई रैलियाँ आयोजित करने के लिये

- इन ग्रुप्स के लिये बसें उपलब्ध करायी जायेंगी, मोदी की यात्रा के दौरान प्रदर्शन करने, काले झण्डे दिखाने व नारेबाजी करने और विभिन्न स्थलों पर आने-जाने के लिये।
- न्यूज एजेंसियों में प्रकाशित खबरों के अनुसार, आई.एस.आई. ने लोगों को ठेका भी दिया है, ट्विटर पर मोदी विरोधी ट्रैन्ड्स वायरल करने के लिये।
- सण्डे गार्डियन अखबार के अनुसार इण्डियन अमेरिकन मुस्लिम काउन्सिल, एक आई.एस.आई. समर्थक ग्रुप, को इन आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।
- जिस दिन मोदी यू.एन. में इन्टरनैशनल योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, उस दिन, 21 जून को आई.एस.आई. प्रेरित ग्रुप्स ने ''हाऊडी डैमोक्रेसी'' कार्यक्रम आयोजित किया है, ''भारत में बढ़ते अन्याय की घटनाओं'' की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की तीन दिन की आसन्न यात्रा से संबंधित धूमधाम एवं जोश-खरोश अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका है। अमेरिका के कानून-निर्माताओं और नागरिकों, खासतौर से भारतीय-अमेरिकनों ने इसे एक ''ऐतिहासिक'' अवसर बताया है।

लेकिन इस यात्रा से सभी खुश हों- ऐसा भी नहीं है। कम से कम भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान तो इससे बिलकुल भी खुश नहीं है। अमेरिकन सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि उन्हें ऐसी खुफिया सूचनाएं मिल रही हैं कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. मोदी की यात्रा में बाधा डालने के लिये पूरा जोरी लगा रही है। उसकी साफ तौर पर कोशिश है कि भारत-अमेरिका के बीच गहरे हो रहे रिश्तों पर देश की अस्वीकृति प्रदर्शित हो।

खुफिया सूत्रों के हवाले से सुरक्षा एजेंसियाँ कह रही हैं कि आई.एस.आई. ने अमेरिका की धरती पर काम कर रहे खालिस्तान-समर्थक संगठनों तथा भारत के खिलाफ काम कर रहे अन्य कई ग्रुपों के साथ मीटिंग की हैं। इन सूत्रों के अनुसार, आई.एस.आई. ने इन खालिस्तान-समर्थक तथा भारत-विरोधी ग्रुपों को बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराया है ताकि वे योजनाएं बना सकें तथा मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान रैलियाँ आयोजित कर सकें।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि खालिस्तानी आंदोलन अभी जीवित है तथा अमेरिका में इसकी गतिविधियाँ चल रही हैं। इसकी अभी बिल्कुल ताजा गतिविधि के अन्तर्गत, सेनफ्रान्सिस्को-स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास की दीवार खराब कर दी गई थी। यह सब उस समय किया गया था, जब अमृत सिंह की तलाश चल रही थी।

2021 में, अमेरिका के शीर्ष थिंक-टैंक हड़सन इन्स्टीट्यूट ''पाकिस्तान'स डीस्टैबलाइजेशन प्ले बुक: खालिस्तानी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प. बंगाल पंचायत चुनाव से केन्द्रीय बल नहीं हटेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। सुप्रीम कोर्ट ने प. बंगाल के पंचायत चुनाव में केन्द्रीय बल तैनात किए जाने के हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इन्कार कर दिया और कहा कि चुनाव हिंसा का लाइसैंस नहीं हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनाव में केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को कायम रखा और इसके खिलाफ दायर प. बंगाल राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और मनोज मिश्रा की अवकाश बैंच ने आदेश दिए कि, ''हाई कोर्ट का आदेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)